

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 9/2018

1. सुबराती, आयु 75 साल
2. अलादीन खां, आयु 78 वर्ष पुत्रगण स्व0 जुमर्दी, जाति तेली, निवासी समस्त इस्लामपुर, तहसील व जिला झुंझुनू (राज0)
3. जाकिर हुसैन आयु- साल पुत्र स्व जाफर अली, जाति तेली
4. शकुरन बानो आयु- साल पत्नि स्व0 जाफर अली, जाति तेली, निवासीगण समस्त इस्लामपुर, तहसील व जिला झुंझुनू (राज0)

— अपीलान्त

बनाम

1. मंगेज सिंह पुत्र रामदेवा, जाति मीणा, निवासी मरोत, तहसील व जिला झुंझुनू (मृतक)
1/1 श्रीमती बादामी पत्नि मृतक मंगेज सिंह
1/2 मदन आयु 50 साल पुत्र मृतक मंगेज सिंह
1/3 गोकुल आयु 45 साल पुत्र मृतक मंगेज सिंह
1/4 मनोज आयु 35 साल पुत्र मृतक मंगेज सिंह
समस्त जाति मीणा, निवासीगण ग्राम मरोत, तहसील व जिला झुंझुनू।
2. तहसीलदार, झुंझुनू, तहसील व जिला झुंझुनू।
3. इमामुदीन पुत्र स्व0 जुमर्दी जाति तेली, निवासी ग्राम इस्लामपुर, तहसील व जिला झुंझुनू।
4. शेर मोहम्मद पुत्र स्व0 जुमर्दी जाति तेली, निवासी ग्राम इस्लामपुर, तहसील व जिला झुंझुनू।
5. यासीन पुत्र स्व0 जाफर अली, जाति तेली, निवासी ग्राम इस्लामपुर, तहसील व जिला झुंझुनू।

— रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश व निर्णय तहसीलदार झुंझुनू बमुकदमा उनवानी मंगेज सिंह बनाम सुबराती आदि अ0धा0 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 29.04.2013

उपस्थित:-

1. श्री फैयाज अहमद, एडवोकेट- अपीलान्तस की ओर से।
2. श्री संदीप बिजारणिया, एडवोकेट- रेस्पोंडेन्ट सं0 1/2 की ओर से।
3. श्री राजेश पूनियां व संदीप बिजारणिया, एडवोकेट- रेस्पोंडेन्ट सं0 1/3 व 1/4 की ओर से।
4. श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक -रेस्पोंडेन्ट सं0 2 की ओर से।

आदेश

दिनांक 27.06.2022


पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपीले तहसीलदार झुंझुनू के निर्णय दिनांक 29.04.2013 के विरुद्ध मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 एवं प्रार्थना पत्र स्थगन के प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपीलान्तगण की ओर से अपील निम्न प्रकार पेश है कि मंगेज सिंह द्वारा अदालत मातहत मे प्रस्तुत परिवादी अ0धा0 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रार्थना पत्र मे दर्ज अनुसार ख0न0 610, 611, 612 वाके ग्राम इस्लामपुर की सरहद को पैतृक एवं स्वयं अर्जित दर्ज

जिला कलक्टर झुंझुनू

किया है किन्तु प्रार्थना पत्र में यह कतई स्पष्ट नहीं किया है कि उक्त अनुसार कौनसी व कितनी भूमि स्वअर्जित है। स्वयं अर्जित किस प्रकार से है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र में उक्त सभी तथ्य वेग दर्ज है जिनके आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार करना अवैध व अवैधानिक है। प्रार्थना पत्र में उक्त भूमि व गैरसायलान ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है। गैरसायलान ने उक्त भूमि पर पत्थर, चिकनी मिट्टी व पानी का हौज बना रखा है दर्ज किया है जो निराधार व गलत है। यह तमाम तथ्य भी प्रार्थना पत्र में पूर्णतया वेग एवं अस्पष्ट दर्ज किये हैं क्योंकि गैरसायलान में किसी गैरसायलान ने किस समय यानि कब-कब क्या कार्य कर अतिक्रमण किया है ऐसा कुछ भी दर्ज नहीं किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार करना कानूनन कतई अवैध व अवैधानिक है। प्रार्थना पत्र में ख0न0 609 गैर मुमकीन रास्ता है उस पर भी अतिक्रमण करके अपनी भूमि में मिला लिया है बिल्कुल गलत दर्ज किया है। उक्त रास्ते को प्रार्थी के कब्जे, काश्त की भूमि के खसरा नम्बर 611 कुल रकबा 8.9 हैक्टर में डाल दिया है लिखना भी पूर्णतया गलत है। ख0न0 611 राजस्व रिकार्ड में दर्ज अनुसार ही रास्ता है एवं जिस पर ग्रेवल सडक निर्माण भी हुआ है ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र में दर्ज उक्त तथ्य स्वयं ही पूर्णतया झूठ व गलत दर्ज करना साबित हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार करना अवैध व अवैधानिक होना स्पष्ट हो जाता है। प्रार्थना पत्र में परिवारी ने गैरसायलान को कई बार लिखित व मौखिक निवेदन किया कि अपनी काश्तकारी व रेवन्यू रिकार्डेड खातेदारी भूमि को अतिक्रमण हटाकर मुक्त कर दे लेकिन गैरसायलान परिवारी की उक्त भूमि को मुक्त करने की बजाय ज्यादा अतिक्रमण कर रहे हैं तथा उक्त परिवारी की कब्जे व काश्त की भूमि से हरे पेड़ काटने की फिराक में है लिखना भी नितान्त व पूर्णरूप से झूठ एवं बनावटी बातें मनगढन्त दर्ज की है। परिवारी ने अपने उक्त कथन दर्ज करने में कहीं भी कोई समय, दिनांक, महिना, वर्ष कुछ भी दर्ज नहीं किया है। लिखित का कोई सबूत परिवार के साथ पेश नहीं किया है। किस गैरसायलान को कब और किस जगह पर क्या कहा गया है कुछ भी दर्ज नहीं किया है। फिर परिवारी के कब्जे, काश्त की भूमि से हरे पेड़ काटने की बात लिखना कितना हास्यास्पद है कि एक तरफ परिवारी अपनी काश्त की भूमि पर गैरसायलान द्वारा अतिक्रमण करना दर्ज करता है दूसरी तरफ वह अपने कब्जे काश्त की भूमि में से हरे पेड़ काटना दर्ज करता है। ऐसी स्थिति में गैरसायलान का कब्जा व अतिक्रमण करना व उसे हटाने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसके अलावा हरे पेड़ काटने के संबंध में भी अलग से प्रावधान है जिनके तहत कोई प्रार्थना पत्र या कार्यवाही क्यों नहीं की गई न्यायालय द्वारा विचारणीय बात है। ज्यादा अतिक्रमण कर रहे हैं दर्ज करना लेकिन ज्यादा अतिक्रमण कैसे कर रहे हैं कुछ नहीं लिखना तथ्यों की मनगढन्त कहानी का होने का स्पष्ट सबूत है। प्रार्थना पत्र में गैरसायलान ने परिवारी को एलानियां धकमी दी कि उक्त विवादित भूमि हमारी है। इस बार हमारा ही कब्जा रखेंगे लिखना भी नितान्त झूठ एवं आधारहीन है इस धमकी के संबंध में भी प्रार्थना पत्र में गैरसायलान में से किस-किसने किस जगह परिवारी को उक्त धमकी दी कुछ दर्ज नहीं किया है। अप्रार्थीगण में शकूरन बानो अपीलान्ट नं0 4 औरत जात है जो पर्दानशीन घरेलू औरत है। बेवा है उसका घर से कहीं बाहर आने-जाने का ही बिना विशेष कारण संभव नहीं है जबकि परिवारी तो गांव मरोत का रहने वाला है। इस्लामपुर निवासी भी नहीं है। इतने गैरसायलान में इमामुदीन तो खेतडी नौकरी करने वाला है। अन्य गैरसायलान भी अलग-अलग कार्यों में व्यस्त रहने वाले हैं। उससे स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र बिल्कुल वेग, आधारहीन व मनगढन्त तथ्य दर्ज कर पेश किया गया है जिसे स्वीकार करना कानूनन अवैध व अवैधानिक है। प्रार्थना पत्र में गैरसायलान उक्त परिवारी की कब्जे, काश्त की भूमि पर पुख्ता अवैध निर्माण कार्य करके अतिक्रमण कर लिया है दर्ज करना भी पूर्णतया झूठ व मनगढन्त दर्ज किया है। क्योंकि परिवारी प्रार्थना पत्र में कब्जा व काश्त अपना दर्ज करता है जबकि कार्यवाही गैरसायलान को अतिक्रमी बताकर बेदखली का कराना चाहता है तो दोनों तथ्य अपने आप में विरोधाभासी होने से भी प्रार्थना

पत्र अस्वीकार्य हो जाता है। प्रार्थना पत्र में दर्ज करना 183 बी की कार्यवाही किया जाना न्यायोचित दर्ज करना भी गलत है। प्रार्थना पत्र में दर्ज अनुसार तथ्यों के मध्यनजर प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया खारिज होने योग्य होने के बावजूद स्वीकार किया जाना अवैध व अवैधानिक है। अदालत मातहत ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दर्ज अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 के नोटिसों की तामिल मानकर जो कार्यवाही व आदेश निर्णय जैसे अपील पारित किया है वह कानूनन पूर्णतया शून्य एवं अप्रभावी है क्योंकि प्रार्थीगण संख्या 1 सुबराती अप्रार्थी संख्या 5 शकूरन बानो की कोई तामिल व्यक्तिशः अदालत मातहत की कार्यवाही मिसल में मौजूद नहीं है। बल्कि स्पष्ट रूप से उक्त तामिल अप्रार्थी संख्या 2 शेर मोहम्मद पर की जाना रिकार्ड से पता चला है। लेकिन अप्रार्थी संख्या 2 शेर मोहम्मद पर की गई तामिल किसी भी रूप में अप्रार्थीगण संख्या 1, 3, 4, 5 पर तामिल होना कानूनन मानना शून्य अप्रभावी है। अप्रार्थी संख्या 5 पत्नि स्व० जाफर अली को दो लडके यासीन व जाकिर हुसैन भी है जिन्हें भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। अधा० 183 बी के तहत कार्यवाही में मियाद का कानूनन अहम बिन्दू है जिस पर किसी भी तरह से कोई भी ध्यान अदालत मातहत में नहीं दिया है। अदालत मातहत में जैसे अपील निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली में परिवादी, पटवारी हल्का या किसी अन्य गवाह का कोई भी बयान दर्ज नहीं कर उक्त कार्यवाही करने में कानूनन बड़ी भूल की है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भी एकपक्षीय व गलत व कानूनन अप्रभावी है। उक्त रिपोर्ट की अप्रार्थीगण को कोई सूचना देकर न तो उनकी उपस्थिति में बनाई गई है तथा ना ही सही पेश की है। अप्रार्थीगण की खातेदारी में ख०न० 608 भूमि को ख०न० 610, 611 व 612 के सीमा लगती दर्ज किया है जो पूर्णतया गलत है। साथ में प्रस्तुत नक्शा ट्रेस भी अधूरा प्रस्तुत किया है जिससे परिवाद में दर्ज तथ्य व पटवारी हल्का की रिपोर्ट में दर्ज तथ्य कतई मेल नहीं खाते हैं। पटवारी हल्का ने परिवाद दर्ज अनुसार किसी भी निर्माण कार्य के संबंध में कुछ भी नहीं लिखा है ऐसी स्थिति में उक्त रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 10.10.2012 पूर्णतया कानून शून्य, अप्रभावी व अमान्य है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से ही ख०न० 608 के खातेदारी में यासीन व जाकिर हुसैन का नाम आया है जिनको पक्षकार नहीं बनाया जाना पूर्णतया साबित है। प्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट के नाम ख०न० 610 की खातेदारी गलत दर्ज है जबकि उक्त भूमि अपीलान्ट्स के पूर्वज जुमर्दी खां की कब्जा, काश्त अधिकार की थी जिस पर विरासतन अपीलान्ट्स काश्त, काबिज खातेदार है। यदि राजस्व अधिकारी या कर्मचारी की गलती या भूल का गलत रिकार्ड बन गया है तो उससे प्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट्स को कोई अधिकार खातेदारी, काश्त, कब्जा प्राप्त नहीं होता है। उक्त सभी तथ्य अदालत मातहत में पूर्ण अवसर मिलने पर प्रस्तुत किये जायेंगे। अतः अपील अपीलान्ट्स पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर आदेश व निर्णय जैसे अपील निरस्त फरमाया जावे। पूर्ण अवसर अपीलान्ट्स को जबाब व साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद विधि सम्मत आदेश पारित करने का आदेश फरमाया जावे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि परिवादी मंगेज सिंह द्वारा अदालत मातहत में प्रस्तुत परिवादी अधा० 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रार्थना पत्र में दर्ज अनुसार ख०न० 610, 611, 612 वाके ग्राम इस्लामपुर की सरहद को पैतृक एवं स्वयं अर्जित दर्ज किया है किन्तु प्रार्थना पत्र में यह कतई स्पष्ट नहीं किया है कि उक्त अनुसार कौनसी व कितनी भूमि स्वअर्जित है। स्वयं अर्जित किस प्रकार से है। अप्रार्थीगण में शकूरन बानो अपीलान्ट नं० 4 औरत जात है जो पर्दानशीन घरेलू औरत है। बेवा है उसका घर से कहीं बाहर आने-जाने का ही बिना विशेष कारण संभव नहीं है जबकि परिवादी तो गांव मरोत का रहने वाला है। इस्लामपुर निवासी भी नहीं है। इतने गैरसायलान में इमामुदीन तो खेतडी


जिला कलेक्टर झुन्झुनूं

नौकरी करने वाला है। अन्य गैरसायलान भी अलग-अलग कार्यों में व्यस्त रहने वाले हैं। प्रार्थना पत्र में गैरसायलान उक्त परिवादी की कब्जे, काश्त की भूमि पर पुख्ता अवैध निर्माण कार्य करके अतिक्रमण कर लिया है दर्ज करना भी पूर्णतया झूठ व मनगढन्त दर्ज किया है। अदालत मातहत ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दर्ज अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 के नोटिसों की तामिल मानकर जो कार्यवाही व आदेश निर्णय जैसे अपील पारित किया है वह कानूनन पूर्णतया शून्य एवं अप्रभावी है क्योंकि प्रार्थीगण संख्या 1 सुबराती अप्रार्थी संख्या 5 शकूरन बानो की कोई तामिल व्यक्तिशः अदालत मातहत की कार्यवाही मिसल में मौजूद नहीं है। बल्कि स्पष्ट रूप से उक्त तामिल अप्रार्थी संख्या 2 शेर मोहम्मद पर की जाना रिकार्ड से पता चला है। लेकिन अप्रार्थी संख्या 2 शेर मोहम्मद पर की गई तामिल किसी भी रूप में अप्रार्थीगण संख्या 1, 3, 4, 5 पर तामिल होना कानूनन मानना शून्य अप्रभावी है। अप्रार्थी संख्या 5 पत्नि स्व० जाफर अली को दो लडके यासीन व जाकिर हुसैन भी हैं जिन्हें भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट के नाम ख०न० 610 की खातेदारी गलत दर्ज है जबकि उक्त भूमि अपीलान्ट्स के पूर्वज जुमर्दी खां की कब्जा, काश्त अधिकार की थी जिस पर विरासतन अपीलान्ट्स काश्त, काबिज खातेदार है। यदि राजस्व अधिकारी या कर्मचारी की गलती या भूल का गलत रिकार्ड बन गया है तो उससे प्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट्स को कोई अधिकार खातेदारी, काश्त, कब्जा प्राप्त नहीं होता है। अपीलान्ट्स को अदालत मातहत द्वारा न तो समुचित रूप से नोटिस तामिल करवाये गये एवं न ही अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट्स को सुना गया। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर आदेश व निर्णय जैसे अपील निरस्त फरमाया जावे या विधिसिम्मत पुनः सुनवाई हेतु अदालत मातहत को रिमाण्ड की जावे।

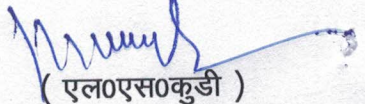
विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट सं० 1/2 ने बहस के दौरान वकील अपीलान्ट्स के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील 4-5 साल बाद पेश की गई है जो अन्दर मियाद नहीं है। अपीलान्ट्स सगे भाई जो एक ही परिवार में रहते हैं। अपीलान्ट का यह कथन गलत है कि उन्हें अदालत मातहत द्वारा समुचित रूप से तामिल नहीं करवाई गई एवं अदालत मातहत द्वारा उनको सुना नहीं गया। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर बाद जांच निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारीज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट सं० 1/2, 1/3 व 1/4 ने बहस के दौरान वकील अपीलान्ट्स के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील 4-5 साल बाद पेश की गई है जो अन्दर मियाद नहीं है। अपीलान्ट्स द्वारा प्रा०प० दफा 5 में देरी के कारणों को स्पष्ट नहीं किया गया है। अपीलान्ट्स सगे भाई जो एक ही परिवार में रहते हैं। अपीलान्ट का यह कथन गलत है कि उन्हें अदालत मातहत द्वारा समुचित रूप से तामिल नहीं करवाई गई एवं अदालत मातहत द्वारा उनको सुना नहीं गया। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर बाद जांच निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारीज फरमाई जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट सं० 2 ने वकील अपीलान्ट्स के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट्स द्वारा अनुसूचित जन जाति की भूमि पर अवैध कब्जा करने पर बाद जांच उचित आदेश पारित किये गये हैं। अदालत मातहत का आदेश विधिसिम्मत है। स्वर्ण जाति के व्यक्ति को अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः अपीलान्ट्स की अपील खारीज फरमाई जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 29.04.2013 यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट्स के विरुद्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर बाद जांच समुचित निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट्स जो कि स्वर्ण जाति के व्यक्ति है को अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट्स को सुना जाकर समुचित रूप से उचित निर्णय पारित किया गया है। हम अदालत मातहत के निर्णय मे हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 29.04.2013 यथावत रखा जाता है। अपील खारिज होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं